



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]
No. 203]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2003/श्रावण 31, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2003/SRAVANA 31, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2003

विषय : कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पी.वी.सी. पेस्ट रेजिन के आयात के बारे में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/14/2003-डीजीएडी.—केंमप्लास्ट सनमार लिमि., चेन्नई ने सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क आकलन एवं संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच शुरु करने तथा पाटन रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

1. विद्याराधीन उत्पाद: वर्तमान मामले में जांचाधीन उत्पाद पोली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन है, जिसे पोली विनाइल क्लोराइड रेजिन (इमल्सन ग्रेड)

अथवा पी०वी०सी० पेस्ट रेजिन (जिसे आगे सम्बद्ध वस्तु) भी कहा गया है । के नाम से भी जाना जाता है । विनायल क्लोराइड मोनोमर (बीसीएम) से इसका उत्पादन होता है और बीसीएम उत्पादन ईडीसी से किया जाता है जिसके लिये बाद में प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में क्लोरिन की जरूरत होती है । इसका उत्पादन और बिक्री सफेद/भूरे पावडर में की जाती है, जो, “के वेल्ज” में भिन्न-भिन्न होते हैं । विभिन्न ग्रेड तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है । इसका उपयोग कृत्रिम चमड़े (रेकसीन) कोटेड फ़ैब्रिक, तिरपालों, कनवेयर बेल्टिंग, खिलानों, आटोमोटिव सालेन्ट और आसंजकों आदि में किया जाता है । पी०वी०सी० पेस्ट रेजिन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियमों में उपशीर्ष संख्या 39042210 के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं । यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि आयातों की निकासी अनेक वर्गीकरणों में की गई है । 39042110 के अन्तर्गत वर्गीकृत पोलीविनायिल क्लोराइड (ससपेन्सन ग्रेड) सम्बद्ध वस्तु से अलग है और इसे विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया गया है । जांच की शुरुआत विचाराधीन उत्पाद के संबंध में की गई है भले ही इस वर्गीकरण के अन्तर्गत इसका आयात किया गया है, वह कुछ भी हो सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और जांच के क्षेत्र पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

2. घरेलू उद्योग की स्थिति

यह याचिका मैसर्स केम प्लास्ट सनमार लिमि० चेन्नई द्वारा दायर की गई है । पी०वी०सी रेजिन मैन्युफैक्चरर्स एसो० (प्रेमा) के अनुसार भारत में पी०वी०सी० पेस्ट रेजिन के केवल दो प्रमुख उत्पादक अर्थात् मैसर्स केम प्लास्ट सनमार लिमि० और मै० पिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमि० हैं । याचिकाकर्ता भारत में संबंधित वस्तु का एक प्रमुख उत्पादक हैं जो भारत में संबंधित वस्तु के एक बड़े भाग का उत्पादन करता है । सम्बद्ध वस्तु के एक अन्य उत्पादक मैसर्स फिनोलेक इंडस्ट्रीज ने याचिका का समर्थन किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता नियम 2 ख के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और याचिकाकर्ता उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 (3) (क) के अनुसार याचिका दायर करने के आधार संबंधी मानदंड को पूरा करता है ।

3. शामिल देश

मौजूदा जांच में शामिल देश/क्षेत्र कोरिया गणराज्य, साउदी अरब और यूरोपीय संघ जिन्हें आगे संबंध देश/क्षेत्र कहा गया है।

4. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु कोरिया गणराज्य, साउदी अरब और यूरोपीय संघ के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबंध वस्तु और सम्बद्ध देश/क्षेत्र से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच के परियोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को उपर्युक्त नियमावली के अर्थ के भीतर संबंध देश/क्षेत्र से आयातित उत्पाद के समान वस्तुओं के रूप में माना जा रहा है।

5. सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने हैरीमान कैम्पसल्ट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पत्रिका अर्थात् “विनायल क्लोराइड” में सूचित घरेलू कीमतों के आधार पर यूरोपीय संघ में संबंध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा किया है। इस पत्रिका को इस व्यापार में अन्तराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत और प्रमाणित पत्रिका होने का दावा किया गया है। प्राधिकारी ने उक्त पत्रिका में प्रकाशित घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर यूरोपीय संघ में संबंध वस्तु को प्रथम दृष्टया स्वीकार किया है। जहां तक कोरिया गणराज्य और साउदी अरब का संबंध है, याचिकाकर्ता ने उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य के दावा किया है जो निर्यातक देश के घरेलू बाजार में ईडीसी जो की संबंध वस्तु के उत्पादन हेतु प्रमुख सामग्री है कि की कीमतों पर आधारित है क्योंकि विनायल क्लोराइड में यह उल्लेख करते हुए हैरीमान कैम्पसल्ट द्वारा सूचना दी गई है कि उक्त पत्रिका अथवा अन्य प्रकाशित पत्रिकाओं में इन देशों की घरेलू कीमतों को सूचित नहीं किया जाता है और वास्तविक बिक्री कीमतें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। प्राधिकारी ने

बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों के अनुसार उचित लाभ को जोड़ने के बाद उत्पादन की परिकल्पित लागत के आधार पर कोरिया गणराज्य और साउदी अरब में सम्बद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्टया विचार किया है।

6. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ता ने आकड़ों के गौण स्रोतों अर्थात् मैसर्स इन्टरनेशनल विजनेश इनफारमेशन सर्विस, बम्बई, जिनके आंकड़े सीमाशुल्क दैनिक सूची पर आधारित हैं, से सौदेवार सूचना के आधार पर संबद्ध देश/क्षेत्र से निर्यात की कीमत निर्धारित की है। कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत निकालने के लिये समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, निर्यात के देश में अन्तर्देशीय परिवहन पत्तन हैंडलिंग और पत्तन प्रभारों के लिये समायोजनों का दावा किया गया है।

7. पाटन मार्जिन -

इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश/क्षेत्र में सम्बद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देश/क्षेत्र के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

9. क्षति एवं कारणात्मक संबध -

याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित विभिन्न मापदंडों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है। उन्होंने संबद्ध देशों में निर्यातकों द्वारा सृजित की गई अतिरिक्त क्षमताओं का उल्लेख किया है और वास्तविक क्षति के खतरे के कारण के रूप में संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास अधिक वस्तु सूचियों का उल्लेख किया है। संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि, आयात कीमत की गिरावट, कुल मांग के संबंध में संबद्ध देशों के हिस्से में वृद्धि और याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में गिरावट, निवेश में कम आय, लाभप्रदता और क्षमता उपयोग में गिरावट, नकारात्मक नकदी प्रवाह, कीमत कटौती, कीमत ह्रास, कीमत स्थिरीकरण जैसे अन्य मापदंडों से सामूहिक और संचयी रूप से प्रथम दृष्टया यह पता

चलता है कि संबंध देश/क्षेत्र से संबंध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और उसे वास्तविक खतरा बना हुआ है।

9. पाटनरोधी जांच का आरंभ

उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबंध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबंध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटन-रोधी जांच आरंभ करते हैं।

10. जांच की अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2002 से 30 जून 2003 तक की है।

11. सूचना देना

इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले संबंध देश के निर्यातकों और भारत के आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबंध शुल्क निदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011 को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं।

उपरोक्त नियम को नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और प्रतिविधिक उपभोक्ता संगठनों, जो पाटन, क्षति और कारणात्मकता के संबंध में जांच के लिए अनिवार्य सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, को भी अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।

12. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने

की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी । यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

13. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2003

Subject : Initiation of Anti-dumping Investigations concerning Import of PVC Paste Resin Originating in or exported from Korea RP, Saudi Arabia and European Union.

No. 14/14/2003-DGAD.—Chemplast Sanmar Limited, Chennai, has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Poly Vinyl Chloride Paste Resin originating in or exported from Korea RP, Saudi Arabia and European Union and have requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under investigation in the present case is Poly Vinyl Chloride Paste Resin also known as Poly Vinyl Chloride Resin (Emulsion grade) or PVC Paste Resin (herein after also referred to as subject goods). It is produced from Vinyl Chloride Monomer (VCM) and VCM is produced from EDC, which in turn require chlorine as major raw material. It is produced and sold in white/off white powder. It is produced in a number of grades, which differ in "K values". Various grades are technically and commercially substitutable. It is used in the artificial leather (Rexene), coated fabrics, Tarpaulins, conveyor belting, Toys, Automotive sealant and adhesives etc. PVC Paste resin is classified under subheading no 39042210 in the Customs Tariff Act though the petitioners have claimed that the imports have been cleared in a number of classifications. The Poly Vinyl Chloride (suspension grade) classified under 39042110 is different from the subject goods and is not included under product under consideration. Investigations are being initiated with respect to product under consideration irrespective of the classification under which they are being imported. Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of investigations.

2. DOMESTIC INDUSTRY STANDING

The petition has been filed by M/s Chemplast Sanmar Limited, Chennai. As per the PVC Resin manufacturers Association (PREMA), there are only two major producer of the PVC Paste Resin in India i.e M.s Chemplast Sanmar Ltd and M/s Finolex Industries Ltd. The petitioner is a major producer of subject goods in India accounting for a major proportion of the production of the subject goods in India. The other producer of the subject goods M/s Finolex Industries has supported the petition. The Authority notes that the petitioner constitutes a domestic Industry within the meaning of the rule 2(b) and the petitioner satisfies the criteria of standing to file the petition in terms of Rule 5(3)(a) of the Rules supra.

3. COUNTRIES INVOLVED

The countries/territory involved in the present investigation are Korea RP, Saudi Arabia and European Union. (hereinafter also referred to as subject countries/territory).

4. LIKE GOODS

The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from Korea RP, Saudi Arabia and European Union. There is no significant difference in the subject goods

produced by the petitioner and those exported from subject countries/territory. Petitioner claims that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of present investigation, the goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles of the product imported from the subject countries/territory within the meaning of the Rules, supra.

5. NORMAL VALUE

The Authority notes that the petitioner has claimed normal value of subject goods in European Union on the basis of domestic prices reported in the published journals namely "Vinyl Chloride" by Harriman Chemsult Limited which has been claimed as internationally acknowledged and authentic journal in this trade. The Authority has prima facie accepted the normal value of the subject goods in the European Union on the basis of the domestic selling prices as published in the journal. With regards to Korea RP and Saudi Arabia, the petitioner has claimed the normal value on the basis of the constructed cost of production which is based on the prices of the EDC in the domestic market of the exporting country which is a major raw material for the production of the subject goods as reported by Harriman Chemsult in "Vinyl Chloride" citing that domestic prices for these countries are not reported in the said journal or other published journals and actual selling prices are not publicly available. The Authority has prima facie considered the normal value of the subject goods in Korea RP and Saudi Arabia on the basis of constructed cost of production after addition of selling, general and administrative expenses along with reasonable profit as per the data made available by the petitioner.

6. EXPORT PRICE

The Petitioner has determined the export price from the subject countries/territory based on the transaction wise information from the secondary data sources, i.e. M/s International Business Information Service, Mumbai whose data is based on the Customs Daily List. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation in the country of exports, port handling and port charges to arrive at the Export Price at ex-factory level.

7. DUMPING MARGIN

There is, prima facie, evidence that Normal Value of the subject goods in the subject countries/territory is significantly higher than the ex-factory export price indicating prima facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries/territory.

8. INJURY AND CAUSAL LINK

Petitioner has furnished information on various parameters relating to material injury and threat of material injury to the domestic industry. They have cited excess capacities created by the exporters in the subject countries and exporters being saddled with the higher inventories in the subject countries as the reason for threat of material injury. Other parameters such as increase in volume of imports from subject countries, decline in the import prices, rise in the share of the subject countries in relation to total demand, and decline in the markets share of the petitioner, low return in investment, decline in the profitability and capacity utilization, negative cash flow, price undercutting, price depression and price suppression, prima facie, indicate collectively and cumulatively that the domestic industry has suffered material injury and is facing threat of material injury on account of dumping of subject goods from subject countries/territory.

9. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

10. PERIOD OF INVESTIGATION

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st October 2002 to 30th June 2003.

11. SUBMISSION OF INFORMATION

The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi – 11 00 11.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

237261/03—2

12. TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

13. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interest party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority